

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक-03/06/2025

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR), हैदराबाद में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स (CoE) की स्थापना हेतु 05 करोड रुपये का मनोनयन के आधार पर अंशदान की स्वीकृति एवं उक्त राशि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद को विमुक्त करने की स्वीकृति ।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, हैदराबाद के पत्रांक CGARD/Trg/18-19/MVR(E7232) दिनांक 17.10.2024 (अनुलग्नक-1) द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद एवं राज्य सरकार के सहयोग से आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स (CoE) की स्थापना हेतु अनुरोध किया गया है ।

2. राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के अंतर्गत नागरिक सेवाओं के निष्पादन (Delivery of Citizen Services) को अधिक प्रभावी बनाने हेतु आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस (AI) की तकनीकों का उपयोग किया जाना अपेक्षित है । आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स (CoE) की स्थापना के द्वारा कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं स्वयं सहायता समूहों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है । इस संदर्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद एवं राज्य सरकार के सहयोग से Hub-and-Spokes model के तहत आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स (CoE) की स्थापना की किया जाना प्रस्तावित है।

3. Hub-and-Spokes model के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान हैदराबाद में Hub स्थापित किया जायेगा । राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद में स्थापित Hub राज्य सरकार को आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में अपना सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स (CoE) (as a spoke) स्थापित करने हेतु मार्गदर्शन एवं सहयोग उपलब्ध करायेगा ।

4. राज्य स्तर पर आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स (CoE) की स्थापना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद से समन्वय स्थापित करने हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय आदेश सं0-3315905 दिनांक-30.10.2024 (अनुलग्नक-2) द्वारा नामित किया गया है।

5. सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स (CoE) की स्थापना हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद एवं राज्य सरकार द्वारा वित्तीय लागत एवं प्रशासनिक दायित्वों का वहन किया

जायेगा। इस संबंध में मनोनयन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 05(पाँच) करोड़ रुपये अंशदान उपलब्ध कराया गया है। इस हेतु पूर्व से सृजित बजट शीर्ष अथवा नया बजट शीर्ष खोल कर राशि का उपबंध कराया जायेगा।

6. सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स (CoE) का प्रदर्शन आशा अनुरूप नहीं रहने पर 3 वर्ष के पश्चात 05 करोड़ की राशि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD&PR), हैदराबाद से वापस ली जा सकेगी। (अनुलग्नक-3 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद का पत्रांक- CGARD/Trg/18-19/MVR(E7232) दिनांक-05.03.2025)।

7. इस पर दिनांक-03.06.2025 को हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं.-05 के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

जापांक 4166345 /

पटना, दिनांक- 03/06/2025

प्रतिलिपि- ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित राजपत्र की 100 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भी उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के सचिव

जापांक 4166345 /

पटना, दिनांक- 03/06/2025

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

जापांक 4166345 /

पटना, दिनांक- 03/06/2025

प्रतिलिपि- राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त/अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व परिषद, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

जापांक- 4166345 /

पटना, दिनांक- 03/06/2025

प्रतिलिपि- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका/ वित्त विभाग, बजट शाखा/ योजना एवं विकास विभाग/बजट शाखा, ग्रामीण विकास विभाग/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी/सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जापांक 4166345 /

सरकार के सचिव
पटना, दिनांक- 03/06/2025

प्रतिलिपि- आईटी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव



सत्यमेव जयते

डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आई ए एस
महानिदेशक

Dr. G. Narendra Kumar, IAS
Director General



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

(ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030, तेलंगाना राज्य, भारत.

NATIONAL INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ

(Ministry of Rural Development, Government of India)

Rajendranagar, Hyderabad- 500 030, Telangana State, India.

Tel (O) : 040-24008441, Fax : 040-24015277

E-mail : gnarendra.nird@gov.in

Dt. 17.10.2024

Letter No. CGARD/Trg/18-19/MVR (E7232)

Dear Amrit,

I am writing to seek support for setting up a Centre of Excellence (CoE) in Artificial Intelligence at NIRDPR.

As you would be aware, the Hon'ble Prime Minister of India has mandated that all Government Departments and Institutes of repute should leverage 'Artificial Intelligence (AI) and other emerging technologies' and deploy them, to enhance the efficacy of delivery of Citizen services, under different developmental programs.

Also one fundamental duty mentioned in the Constitution of India, reads "to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement".

In keeping with the vision of the Hon'ble Prime Minister and our collective responsibility under the Constitution, NIRD&PR has resolved to establish a Centre of Excellence in AI to cater to Agriculture, Animal Husbandry, Rural Development, Panchayati Raj and Self Help groups.

The EC of NIRD&PR has in principle approved the establishment of the Center of Excellence (CoE) in AI, as a collaborative effort between NIRDPR and State Governments. NIRDPR and the States will share financial costs and Governance Responsibilities. The CoE will operate on a Hub-and-Spokes model. The Hub established at NIRD&PR, Hyderabad, will guide the State Governments and help establish their own CoEs in AI (as a spoke). The Vision, Mission, Activities, Governance Framework are given in annexure (detailed note on CoE AI).

As Director General, NIRD&PR, it gives me immense pleasure, to invite your State Government to participate in this national endeavor.

We would like to request you to identify a Nodal Officer, preferably in the rank of a Principal Secretary, who will Co-ordinate with NIRD&PR. The officer will articulate State specific needs and priorities. He will represent the state on The Hub.

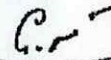
Further, you are requested to contribute Rs.5 Cr. towards the endowment fund for the CoE in AI. NIRD&PR has already committed its share of Rs.5 Cr. to the Endowment Fund.

(contd...2..)

Let us together strive to develop the COE in AI. for 'Vikasit Bharat', which in times to come, should not only cater to all the states in India, but also to Third World countries.

With regards

Yours sincerely,


(G. Narendra Kumar)

Shri Amrit Lal Meena, IAS,
Chief Secretary,
Government of Bihar
Main Secretariat
PATNA - 800015
cs-bihar@nic.in

Copy to

Shri Lokesh Kumar Singh, IAS
Secretary, Rural Development, Govt. of Bihar
Email: rlrsec-bih@nic.in

Proposal for Setting Up :
Centre of Excellence (COE) in AI for Development
at
National Institute of Rural Development & Panchayati Raj

Vision

Leveraging AI technologies and innovative applications for enhancing the effectiveness of development programs by crafting deployable solutions for Rural Development, Panchayat Raj, Agriculture, Animal husbandry and allied sectors.

Mission

- To foster a Centre of Excellence (CoE), with state-of-the art (SOTA) infrastructure, staffed with competent resources to produce Artificial Intelligence based technology solutions that address development challenges.
- To propagate and transfer successful AI solutions to all state governments and other stakeholders in the field of Rural Development and Agriculture.
- To support state governments and other stakeholders in establishing centres at the state level for leveraging AI technologies to find effective solutions to state specific development challenges.
- To collaborate with academia, global institutions and corporate entities and draw upon their expertise and resources to help build the reputation of the centre as a Global Centre of Excellence and Research in AI technologies for development.

Proposed Approach

The Centre of Excellence (CoE) will be a collaborative effort between NIRD and State Governments. NIRD and States will sharing financial costs and governance responsibilities. COE will operate like a Hub-and-Spoke model. This model is designed to ensure that the CoE serves as a central resource (Hub), to provide solutions to select problems impacting many states, while providing tailored support and operational flexibility to individual State Governments (Spokes). This approach is similar to the institutional arrangement of NIRD and SIRDs wherein NIRD acts as a Hub supporting SIRDs as Spokes.

The key features of this model include:

1. Centralized Activities:

- o The CoE (Hub) will house core domain expertise, technical resources, and infrastructure.
- o CoE will provide foresight for AI in Development and assist Ministry of RD &PR, Agriculture and Animal Husbandry in developing appropriate policy frameworks.
- o The CoE will undertake AI-based PoC and prototype projects, after identifying problems common to states.
- o CoE will provide mentoring support to States (Spokes), which participate in CoE as an executive member by making contribution to endowment funds.
- o It will develop best practices, training programs and standardized AI solutions- that can be adopted by the States for large scale roll-out.
- o The Hub will endeavour to replicate AI solution success stories from states across India.

- The Hub will create and maintain a comprehensive repository of AI initiatives and industry solutions, document case studies, create project reports, and research findings to build a knowledge base that can guide future AI projects
2. Decentralized or State-level Activities:
- State Governments (Spokes) will have the autonomy to adapt and implement solutions developed by Hub according to their specific needs and priorities.
 - Each State will be encouraged to develop state-specific AI initiatives and leverage the centralized resources for support and guidance.
 - State-level level Spokes can also undertake AI-based PoC and prototype projects for specific needs of the states and receive technical support from the Hub.
 - For all Spokes, Hub will act as an in-house technical and institutional support resource.
 - The Hub may undertake projects on behalf of states which cannot afford to undertake projects on their own.
3. Financing Arrangements of the Hub:
- A proposed funding mechanism is by the creation of an endowment fund which will have contributions from Government of India (GOI), State Governments and NIRD&PR.
 - The minimum endowment shall be of INR 40 crores and may go up to maximum of INR 100 crores.
 - The participation in the endowment fund will be for a period of 5 years to start with. Participating states will have the option not to continue as part of CoE after a lock-in period of 5 years. If a state decides not to continue the participation then the State may withdraw from the CoE together with their contribution from the endowment fund.
 - The proposed contribution to the fund may be as follows:
 - a. NIRD's minimum contribution will be INR 5 crores,
 - b. Each participating state's minimum contribution will be
 - 5 crores for large states in terms of population
 - For 15 states with lowest population, the minimum contribution is proposed to be INR 2 crores
 - c. Ministry of Rural Development's minimum contribution will be Rs. 10 crores.
 - d. Other National Institutes may also join the CoE by making a contribution of INR 5 crores to the endowment fund.
 - The income generated from the endowment fund will be used to cover the core operational costs of the CoE.
 - All states who do not become members of the CoE in the beginning, can join the CoE as an executive member by making the contribution to the endowment fund.
 - The CoE will be self-sustaining and will not need budgetary support from any stakeholder after three years. During this interim period of three years, shortfall in operational expenses have to be borne by states/stake holders in proportion to their contribution.
 - Endowment fund of the CoE will be managed by an endowment management committee which will be headed by DG NIRD and Director of CoE will be the convenor. There will be due process of consultation with the stakeholders for managing the Endowment Fund.
4. Financing Arrangements of the Spokes (CoE's at States):

The first part of the report deals with the general situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's development.

The second part of the report deals with the economic situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's economic development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's economic development.

The third part of the report deals with the social situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's social development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's social development.

The fourth part of the report deals with the political situation of the country. It is a very interesting and informative study of the country's political development. The author has done a great deal of research and has gathered a wealth of material. The report is well written and is a valuable contribution to the study of the country's political development.

- The CoE at NIRD will provide all technical and institutional assistance to States for establishing State CoE specific to a thematic area or CoE at the state level for which financing, and governance structure will be decided by the States. CoE may charge consultancy charges from State SoE's for undertaking specific state level projects.

5. Collaborative Framework:

- Regular interactions and feedback loops will be established between the Hub and the Spokes to ensure continuous improvement and adoption of AI solutions. AI solutions (proof-of-concept and prototype) developed at the Hub will be available to Spokes at no cost. However, if the beta versions need customization, the Hub will provide technical support, for which a fee may have to be borne by the concerned state.
- Joint workshops, training sessions, and conferences will be organized to facilitate knowledge sharing and collaboration among States.
- Hub will provide full support to Spokes in AI implementations, knowledge sharing and be available as an internal technical and AI domain expert.
- Hub will act as a AI specific in-house consultant to Spokes.

6. Operational Independence of Spokes:

- While the CoE will provide overarching guidelines and support, State Governments will retain operational and tactical independence of Spokes to align CoE activities with their regional development goals.

By adopting this Hub-and-Spoke model, the CoE aims to create a robust and flexible framework that supports State Governments in leveraging AI for Rural Development, Agriculture and Animal Husbandry etc. while maintaining consistency, leveraging shared knowledge and tools, sharing solution domain and quality standards across different States.

Operations Period

The Centre of Excellence (CoE) is envisaged to operate for an initial period of 5 years. This tenure will ensure the establishment and stabilization of the CoE's operations and its integration with the State Governments' initiatives.

Governance Framework

The Governance Framework of the CoE will be designed to ensure collaborative leadership, decision-making, and accountability. The key elements of the governance structure can be as follows:

Steering Committee (Apex Body):

1. Will provide overall strategic direction, approve annual budget and rules of conduct of business of the CoE
2. It will be headed by Director General (DG) of NIRD&PR as chairman of the committee and will have members from participating states, Government of India and other National Institutions which have contributed to the endowment fund
3. The steering committee will necessarily have two Co-Chairpersons nominated by the State Governments to represent the interests of the states and ensure that the CoE's activities are aligned with state-specific needs and priorities.
4. Steering committee will meet at least two times in a year.

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year.

2. The second part of the report deals with the results of the work done during the year. It is divided into two main sections: the first section deals with the results of the work done in the field, and the second section deals with the results of the work done in the laboratory.

3. The third part of the report deals with the conclusions drawn from the results of the work done during the year.

4. The fourth part of the report deals with the recommendations made for the future work.

5. The fifth part of the report deals with the summary of the work done during the year.

6. The sixth part of the report deals with the bibliography.

7. The seventh part of the report deals with the appendix.

8. The eighth part of the report deals with the index.

9. The ninth part of the report deals with the list of figures.

10. The tenth part of the report deals with the list of tables.

5. The Director of the CoE shall be appointed by the Steering Committee to oversee the day-to-day management of the CoE, to provide strategic direction, to coordinate with stakeholders.

Executive Committee:

1. Director of CoE will head the executive committee, and the executive committee will have representatives from NIRD, and other professionals working in the CoE.
2. Approve and monitor execution of programs and projects and ensure that they align with the CoE's mission and objectives.
3. The committee shall approve the appointment of all staff and professionals including Chief Operating Officer (COO) recruited and deployed at the CoE.
4. The committee shall present to steering committee for approval requests for taking on-board domain experts from the States and Government of India
5. The selection of technology partners of the CoE comprising of startup's and IT companies.

Advisory Board:

1. Comprising experts from academia, industry, and government will be established to provide guidance and support to the CoE.
2. This Board will meet periodically to review the CoE's progress, provide feedback, and recommend improvements.
3. Advisory board will meet once in a year

Director:

1. Eligibility Criteria: Serving or retired Indian Administrative Service officer holding rank of additional secretary or above and having worked in the development sector and preferably having a technical background.

Core Team Composition:

Centre of Excellence Team Composition				
Role	Responsibility	No. of Resources	Deployment	Involvement*
Director	- Oversee the day-to-day operations of the CoE - Provide overall strategic direction for the CoE - Coordinate with international and domestic faculty for project development and execution - Lead and manage senior staff, setting performance goals and standards - Oversee budget preparation and approval processes - Report to the Steering Committee on CoE's progress and strategic	1	On-site	Full-Time

	initiatives			
Chief Operation Officer	- Ensure efficient implementation of AI projects and initiatives. - Develop and implement operational policies and procedures - Bring industry expertise to align problem statements to feasible solutions in the technology domain - Lead outreach initiatives with start-up ecosystem - Align CoE objectives with stakeholder needs and opportunities	1	On-site	Full-Time
Senior Consultant (AI)	- Conceptualize and design AI-driven solutions for rural development. - Partner with academic institutions, start-ups, industry leaders, and governmental bodies - Design, prototype, and implement pilot projects.	3	On-site	Full-Time
Consultant Training & Capacity Building	- Conduct Training Need Assessment and training programs for government officials and other stakeholders - Organize workshops and seminars. - Conduct research to identify and develop AI-driven solutions tailored to rural development. - Document case studies, project reports, and research findings.	2	On-site	Full-Time
Consultant Domain Support	- Provide domain-specific inputs for AI solutions. - Consultation with key stakeholders - Study of documents, reports, systems - Formulation &	1	On-site	Full-Time

	documentation requirements, specifications, recommendations, observations as requirements.	of and per			
--	---	------------------	--	--	--

**There shall also be a team of technical IT professionals to be hired by the COE but the composition of that team shall be finalized after stakeholder consultation in keeping with the projects coming into the COE.*

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

आदेश

आओसं० ३३/५९०५

आओवि०-०६-विविध/१३-१७/२०२४

पटना, दिनांक ३०/१०/२०२४

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-CGARD/Trg/18-19/MVR(E7232) दिनांक-17.10.2024 द्वारा सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा A.I(Artificial Intelligence) के क्षेत्र में Centre of Excellence(CoE) की स्थापना प्रस्तावित है। जिसमें NIRD&PR, हैदराबाद, Hub-and-Spokes मॉडल के तहत Hub के रूप में कार्य करेगा।

2. बिहार राज्य अंतर्गत A.I(Artificial Intelligence) में Centre of Excellence(CoE) की स्थापना एवं NIRD&PR, हैदराबाद से समन्वय स्थापित करने हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को नामित किया जाता है।

3. उक्त पर मुख्य सचिव, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक ३३/५९०५

आओवि०-०६-विविध/१३-१७/२०२४

पटना दिनांक ३०/१०/२०२४

प्रतिलिपि:- माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार/ सचिव, बिहार विधान सभा/ सचिव, बिहार विधान परिषद्/ महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/ सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, पटना/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक ३३/५९०५

पटना दिनांक ३०/१०/२०२४

प्रतिलिपि:- महानिदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को उनके पत्रांक-CGARD/Trg/18-19/MVR(E7232) दिनांक-17.10.2024 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव



डॉ. जी. नरेंद्र कुमार, आई ए एस
महानिदेशक

Dr. G. Narendra Kumar, IAS
Director General



राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान

(ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

राजेन्द्रनगर, हैदराबाद - 500 030; तेलंगाना राज्य, भारत.

NATIONAL INSTITUTE OF RURAL DEVELOPMENT & PANCHAYATI RAJ

(Ministry of Rural Development, Government of India)

Rajendranagar, Hyderabad- 500 030, Telangana State, India.

Tel (O) : 040-24008441, Fax : 040-24015277

E-mail : gnarendra.nird@gov.in

Dt. 05.03.2025

Letter No. CGARD/Trg/18-19/MVR (E7232)

Lokesh ji,

Please refer to my earlier letter dt. 17.10.2024 (copy attached) seeking fund for Rs.5 crore towards endowment fund on returnable basis after 3 years, if the CoE performance is lagging.

We are looking forward to your response in this regard.

With regards

Yours sincerely,


(G. Narendra Kumar)

Shri Lokesh Kumar Singh, IAS
Secretary to Govt. of Bihar
Rural Development Department
Email: rlrsec-bih@nic.in